

No. 23/05/2020-R&R
Government of India
Ministry of Power

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg.
New Delhi, 16th June, 2023

To,

- 1 Secretary, MNRE, New Delhi
- 2 Chairperson, Central Electricity Authority, Sewa Bhavan, R.K. Puram, New Delhi
- 3 Secretary, Central Electricity Regulatory Commission (CERC), New Delhi
- 4 Principal Secretaries/Secretaries (Power/Energy) of all State Governments/UTs
- 5 Secretaries of All State Electricity Regulatory Commissions/JERCs.
- 6 Chairman/CMDs of all PSUs under administrative control of Ministry of Power.
- 7 CMD, SECI, New Delhi
- 8 CMDs/MDs of Discoms/Gencos of all State Governments
- 9 CMD, IEX LTD New Delhi & MD/CEO, PXIL, Mumbai/ HPX New Delhi.
- 10 DG, Association of Power Producers, New Delhi.
- 11 President, FICCI, House No. 1, Tansen Marg New Delhi
- 12 President, CII, New Delhi.
- 13 President, PHDCCI, New Delhi
- 14 ASSOCHAM, Chanakyapuri, New Delhi
- 15 Member, PRAYAS Energy Group, Pune
- 16 DG, Electric Power Transmission Association (EPTA), New Delhi
- 17 Chairman Indian Wind Power Association, New Delhi
- 18 Chairman, Indian Wind Turbine Manufacturers Association, New Delhi
- 19 Director General, National Solar Energy Federation of India (NSEFI), New Delhi.
- 20 DG, Solar Power Developers Association, New Delhi.

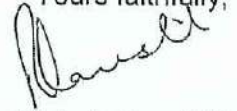
Subject: Electricity (Rights of Consumers) Amendment Rules, 2023.

Sir/Madam,

I am directed to forward herewith the Electricity (Rights of Consumers) Amendment Rules, 2023 for information.

Encl: as above

Yours faithfully,


(Rajesh Kaushik)
Section Officer
011- 23730265

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Minister of Power and NRE, APS to Hon'ble MoSP.
2. SS&FA/AS/All Joint Secretaries/All Chief Engineer/Economic Adviser, MoP.
3. Sr. PPS to Secretary (Power), PS to CE (R&R), All Dir. /All DS, MoP.

Copy to: Technical Director, NIC Cell for uploading on MOP's website under "New Notices" with the heading of "**Electricity (Rights of Consumers) Amendment Rules, 2023**".



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062023-246571
CG-DL-E-15062023-246571

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350]
No. 350]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 14, 2023/ज्येष्ठ 24, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 14, 2023/JYAISHTHA 24, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2023

सा.का.नि. 437(अ).—केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (1), उप धारा (2) के खंड (य) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 में, और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) संशोधन नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है), के नियम 5 के, उप नियम (5) में, निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(5) सभी प्रकार के स्मार्ट मीटरों की दिन में कम-से-कम एक बार दूरस्थ रीडिंग की जाएगी तथा अन्य प्री-पेमेंट मीटरों की, किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक तीन माह में कम-से-कम एक बार रीडिंग की जाएगी तथा ऊर्जा खपत संबंधी डाटा को वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन या शॉर्ट मैसेज सर्विस और इसी तरह की सर्विस आदि के माध्यम से, उपभोक्ता को उपलब्ध कराए जाएंगे। परंतु स्मार्ट प्री-पेमेंट मीटर रखने वाले उपभोक्ताओं को उनके द्वारा की गई खपत और दैनिक आधार पर कम से कम अतिशेष रकम की जांच करने के लिए डाटा एक्सेस प्रदान किया जा सकता है।”

(5क) स्मार्ट मीटरों की संस्थापना के पश्चात, संस्थापना तारीख से पूर्व की अवधि के लिए, स्मार्ट मीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई अधिकतम मांग के आधार पर उपभोक्ता पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(5ख) यदि स्मार्ट मीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई अधिकतम मांग, एक मास में संस्वीकृत भार से अधिक हो जाती है, तो उस बिलिंग चक्र के लिए बिल की गणना वास्तविक रिकार्ड की गई अधिकतम मांग के आधार पर की जाएगी और उपभोक्ताओं को शॉर्ट मैसेज सर्विस या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से गणना में इस परिवर्तन के बारे में सूचित किया जाएगा:

परंतु यह कि संस्वीकृत भार, यदि कोई हो, का पुनरीक्षण वास्तविक रिकार्ड की गई अधिकतम मांग के आधार पर निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) रिकॉर्ड की गई अधिकतम मांग में वृद्धि के मामले में, मासिक अधिकतम मांग में से सबसे कम, जहां रिकॉर्ड की गई अधिकतम मांग एक वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम तीन बार संस्वीकृत भार सीमा से अधिक हो गई है, पुनरीक्षित संस्वीकृत भार के रूप में मानी जाएगी, और वही अगले वित्तीय वर्ष में बिलिंग चक्र से स्वचालित रूप से रीसेट हो जाएगी; और

(ख) अधिकतम मांग में कमी के मामले में, संस्वीकृत भार का पुनरीक्षण संबंधित विनियामक आयोग द्वारा जारी आपूर्ति कोड/मानक प्रचालन क्रिया पद्धतियों के अनुसार किया जाएगा।

3. मूल नियमों में, नियम 8 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

(8क) **टाइम ऑफ डे टैरिफ** - दस किलोवाट से अधिक अधिकतम मांग वाले वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ डे टैरिफ पहली अप्रैल, 2024 से पहले की तारीख से प्रभावी होगा और अन्य उपभोक्ताओं के लिए, कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर, टाइम ऑफ डे टैरिफ पहली अप्रैल, 2025 से पहले प्रभावी बनाया जाएगा; और यह टाइम ऑफ डे टैरिफ, स्मार्ट मीटरों वाले उपभोक्ताओं के लिए, स्मार्ट मीटरों की संस्थापना के ठीक पश्चात प्रभावी हो जाएगा।

परंतु यह कि, दिन की व्यस्ततम अवधि के दौरान वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट टाइम ऑफ डे टैरिफ, सामान्य टैरिफ के 1.20 गुना से कम नहीं होगा और अन्य उपभोक्ताओं के लिए, यह सामान्य टैरिफ के 1.10 गुना से कम नहीं होगा:

परन्तु यह और कि, राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट, दिन के सौर घंटों के लिए टैरिफ, उस श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए सामान्य टैरिफ से कम से कम बीस प्रतिशत कम होगा:

परन्तु यह भी कि सामान्य टैरिफ के ऊर्जा प्रभार घटक पर टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू होगा:

परन्तु यह भी कि व्यस्ततम घंटों की अवधि राज्य आयोग या राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा अधिसूचित सौर घंटों से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण: - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "सौर घंटे" पद से राज्य आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट एक दिन में आठ घंटे की अवधि अभिप्रेत है।

(8ख) **टैरिफ प्रदर्शन** - प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ, वितरण अनुज्ञतिधारी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और उपभोक्ताओं को वितरण अनुज्ञतिधारी की वेबसाइट के साथ-साथ ऊर्जा बिलों या शॉर्ट मैसेज सर्विस या मोबाइल एप्लिकेशन और इसी प्रकार की सर्विस आदि के माध्यम से कम से कम एक मास पूर्व, ईंधन अधिभार और अन्य प्रभारों को छोड़कर, टैरिफ में परिवर्तन अधिसूचित किया जाएगा।"

[फा. सं. 23/05/2020-आरएंडआर]

पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 818(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2020, संख्यांक सा.का.नि. 448 (अ), तारीख 28 जून, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा संख्यांक सा.का.नि. 306(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2023

G.S.R. 437(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (1), clause (z) of sub-section (2) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020, namely:-

1. (1) These rules may be called the Electricity (Rights of Consumers) Amendment Rules, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Electricity (Rights of Consumers) rules, 2020 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 5, for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(5) All types of smart meters shall be read remotely at least once in a day and the other pre-payment meters shall be read by an authorised representative of the distribution licensee at least once in every three months and the data regarding energy consumption shall be made available to the consumer, through website or mobile application or Short Message Service and the like, provided that the consumers having smart pre-payment meters shall also be given the data access for checking their consumption and balance amount atleast on daily basis.

(5A) After the installation of smart meters, no penalty shall be imposed on the consumer, based on the maximum demand recorded by the smart meter, for the period before the installation date.

(5B) In case maximum demand recorded by the smart meter exceeds the Sanctioned Load in a month, the bill, for that billing cycle, shall be calculated based on the actual recorded maximum demand and consumers shall be informed of this change in calculation through Short Message Service or mobile application:

Provided that the revision of the Sanctioned Load, if any, based on the actual recorded maximum demand shall be as under:

- (a) in case of increase in recorded maximum demand, the lowest of the monthly maximum demand, where the recorded maximum demand has exceeded the sanctioned load limit atleast three times during a financial year, shall be considered as the revised Sanctioned Load, and the same shall be automatically reset from the billing cycle in next financial year; and
- (b) in case of reduction of maximum demand, the revision of sanctioned load shall be done in accordance with the Supply codes/ Standard Operating Procedures issued by the respective Regulatory Commission.

3. In the principal rules, after rule 8, the following rules shall be inserted, namely:-

(8A) **Time of Day Tariff.**-The Time of Day tariff for Commercial and Industrial consumers having maximum demand more than ten Kilowatt shall be made effective from a date not later than 1st April, 2024 and for other consumers except agricultural consumers, the Time of Day tariff shall be made effective not later than 1st April, 2025 and a Time of Day tariff shall be made effective immediately after installation of smart meters, for the consumers with smart meters:

Provided that, the Time of Day Tariff specified by the State Commission for Commercial and Industrial consumers during peak period of the day shall not be less than 1.20 times the normal tariff and for other consumers, it shall not be less than 1.10 times the normal tariff:

Provided further that, tariff for solar hours of the day, specified by the State Commission shall be atleast twenty percent less than the normal tariff for that category of consumers:

Provided also that the Time of Day Tariff shall be applicable on energy charge component of the normal tariff:

Provided also that the duration of peak hours shall not be more than solar hours as notified by the State Commission or State Load Despatch Centre.

Explanation:- For the purposes of this rule, the expression “solar hours” means the duration of eight hours in a day as specified by the State Commission.

(8B) **Display of Tariff.**—The tariff for each category of consumers shall be displayed on distribution licensee's website and consumers shall be notified of change in tariff excluding fuel surcharge and other charges, at least one month ahead of time, through distribution licensee's website as well as through energy bills or Short Message Service or Mobile Application and the like."

[F. No. 23/05/2020-R&R]

PIYUSH SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 818(E), dated the 31st December, 2020, *vide* number G.S.R. 448 (E), dated 28th June, 2021 and last amended *vide* number G.S.R. 306(E), dated 20th April, 2022.

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2020

G.S.R. 818(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (z) of sub-section (2) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) “**Act**” means the Electricity Act, 2003;
 - (b) “**applicant**” means an owner or occupier of any premises who files an application form with a distribution licensee for supply of electricity, increase or decrease in sanctioned load or contract demand, change in title or mutation of name, change in consumer category, disconnection or restoration of supply, or termination of agreement, shifting of connection or other services as the case may be, in accordance with the provisions of the Act, rules and regulations made thereunder;
 - (c) “**application**” means an application form complete in all respects in the appropriate format, as specified by the Commission, along with documents and other compliances;
 - (d) “**billing cycle or billing period**” means the period for which regular electricity bills as specified by the Commission, are issued for different categories of consumers by the distribution licensee;
 - (e) “**Commission**” means the State Electricity Regulatory Commission constituted under section 82 of the Act;
 - (f) “**Consumer**” means any person who is supplied with electricity for his own use by a distribution licensee or the Government or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under the Electricity Act, 2003 or any other law for the time being in force and includes any person whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving electricity with the works of a distribution licensee, the Government or such other person, as the case may be;
 - (g) “**days**” means clear working days;
 - (h) “**disconnection**” means the physical separation or remote disconnection of a consumer from the distribution system of the distribution licensee;
 - (i) “**fixed charges**” has the same meaning as per the provisions of the prevailing Tariff Order issued for the distribution licensee by the Commission;
 - (j) “**maximum demand**” means the highest load measured in average kVA or kW at the point of supply of a consumer during any consecutive period of thirty minutes or as specified by the Commission, during the billing period;
 - (k) “**occupier**” means the owner, tenant or person in occupation of the premises where electricity is used or proposed to be used;
 - (l) “**point of supply**” means the point, as may be specified by the State Commission, at which a consumer is supplied electricity;
 - (m) “**prosumer**” means a person who consumes electricity from the grid and can also inject electricity into the grid for distribution licensee, using same point of supply;
 - (n) “**temporary connection**” means an electricity connection required by a person for meeting his temporary needs such as-
 - (i) for construction of residential, commercial and industrial complexes including pumps for dewatering;
 - (ii) for illumination during festivals and family functions;

- (iii) for threshers or other such machinery excluding agriculture pump sets;
- (iv) for touring cinemas, theatres, circuses, fairs, exhibitions, melas or congregations.

(o) “unauthorised use of electricity” has the meaning as assigned to it under section 126 of the Act.

(2) The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act and in absence thereof, the meanings as commonly understood in the electricity supply industry.

3. Rights and Obligations.- It is the duty of every distribution licensee to supply electricity on request made by an owner or occupier of any premises in line with the provisions of Act. It is the right of consumer to have minimum standards of service for supply of electricity from the distribution licensee in accordance with the provisions made in these rules.

4. Release of new connection and modification in existing connection.- (1) The distribution licensee shall prominently display on its website and on the notice board in all its offices, the following; namely:-

- (a) detailed procedure for grant of new connection, temporary connection, shifting of meter or, service line, change of consumer category, enhancement of load, reduction of load or change in name, transfer of ownership and shifting of premises etc;
 - (b) address and telephone numbers of offices where filled-up application forms can be submitted;
 - (c) address of website for online submission of application form;
 - (d) complete list of copies of the documents required to be attached with the application;
 - (e) all applicable charges to be deposited by the applicant.
- (2) Application forms for all type of connections as well as modification in existing connection shall be available at all the local offices of the distribution licensee free of cost as well as on its website for free download.
- (3) The distribution licensee shall create a web portal and a mobile app for submission of online application forms.
- (4) The applicant shall have an option to submit an application form in hard copy form or an electronic means such as online through web portal or mobile app of distribution licensee.
- (5) In case hard copy of the application form is submitted, the same shall be scanned and uploaded on the website as soon as it is received and acknowledgement with the registration number for that applicant shall be generated and intimated to the applicant.
- (6) In case of online application form through web portal or mobile app of distribution licensee, the acknowledgement with the registration number shall be generated on submission of application.
- (7) An application, complete with all the required information, shall be deemed to be received on the date of generation of acknowledgement with registration number. In case of hard copy submission, the acknowledgement with registration number shall be generated within such period as may be specified by the Commission, not exceeding twenty four hours, of receipt of the application, complete with all the required information.
- (8) The application tracking mechanism based on the unique registration number shall be provided by the distribution licensee through web-based application or mobile app or through SMS or by any other mode to monitor the status of processing of the application like receipt of application, site inspection, issuance of demand note, external connection, meter installation and electricity flow.
- (9) For new connections up to a load of 10 kW or such higher load as may be specified by the Commission, the application form shall be accompanied with only two mandatory documents-
- (1) identity proof (i.e. Passport, Aadhar Card etc.) of the applicant; and
 - (2) proof of applicant’s ownership or occupancy over the premises for which new connection is being sought or in the absence of any proof of ownership or occupancy, any other address poof not

given as part of identity proof under (1) above. For new connections beyond the specified load, and modification of existing connection, the Commission shall explicitly specify the documents required to be submitted with the application.

- (10) In case, an agreement is required to be executed between distribution licensee and the consumer, the same shall become the part of the application form and there shall not be any requirement of a separate agreement form.
- (11) The Commission shall specify the maximum time period, post submission of application complete in all respect, not exceeding seven days in metro cities, fifteen days in other municipal areas and thirty days in rural areas, within which the distribution licenses shall provide new connection and modify an existing connection:

Provided that where such supply requires extension of distribution mains, or commissioning of new sub-stations, the distribution licensee shall supply the electricity to such premises immediately after such extension or commissioning or within such period as may be specified by the Commission.

- (12) If a distribution licensee fails to supply electricity within the period specified by the Commission, it shall be liable to a penalty as may be determined by the Commission, which shall not exceed one thousand rupees for each day of default.
- (13) For electrified areas up to 150 kW or such higher load as the Commission may specify the connection charges for new connection shall be fixed on the basis of the load, category of connection sought and average cost of connection of the distribution licensee so as to avoid site inspection and estimation of demand charges for each and every case individually. The demand charges, in such cases, may be paid at the time of application for new connection.

5. **Metering** – (1) No connection shall be given without a meter and such meter shall be the smart pre-payment meter or pre-payment meter. Any exception to the smart meter or prepayment meter shall have to be duly approved by the Commission. The Commission, while doing so, shall record proper justification for allowing the deviation from installation of the smart pre-payment meter or pre-payment meter.

- (2) At the time of seeking a new connection the consumer shall have the option to -
- (a) purchase the meter, MCB or CB and associated equipment himself; or
 - (b) require that the meter, MCB or CB and associated equipment be supplied by the distribution licensee, on payment of applicable charges.
- (3) The distribution licensee shall ensure that tested and sealed meters of approved meter manufacturers are available to consumers for purchase and information of the places from where the consumers can purchase them is made available on its website.
- (4) The meter shall be read at least once in every billing cycle in urban as well as rural areas by an authorised representative of the distribution licensee.
- (5) In case of smart meters, the meters shall be read remotely at least once in every month and in case of other pre-payment meters, the meters shall be read by an authorised representative of the distribution licensee at least once in every three months. The data regarding energy consumption shall be made available to the consumer, through website or mobile App or SMS, etc. Consumers having smart pre-payment meters may also be given the data access for checking their consumption on real time basis.
- (6) For post payment meters, if the meter is inaccessible to the meter reader on two consecutive meter reading dates, the consumer shall have the option to send the picture of the meter indicating the meter reading and date of meter reading through registered mobile or through e-mail. In such a case, distribution licensee may not send any notice or provisional bill to the consumer
- (7) Testing of meters shall be done by the distribution licensee within a period as may be specified by the Commission, not exceeding thirty days, of receipt of the complaint from the consumer about their meter readings not being commensurate with his consumption of electricity, stoppage of meter, damage to the seal, burning or damage of the meter, etc.

- (8) No test fee shall be charged from the consumer at the time of reporting if the meter is found to be defective or burnt due to reasons attributable to the consumer, the consumer shall bear the cost of new meter and test fee shall be charged from the consumer through subsequent bills.
- (9) The distribution licensee shall give a copy of the meter test report to the consumer duly signed by both the distribution licensee or their authorised representatives and the consumer, and retain one such copy as acknowledgment. The distribution licensee shall communicate the date and time for such test to the consumer and convey the said consumer to present at the site for testing. However, if the consumer chooses not to be present at the site for testing, the distribution licensee will carry out such testing and shall give the copy of the meter test report to the consumer for signing.
- (10) In case, during testing, the meter is found to be inaccurate, the excess or deficit charges shall be adjusted in the subsequent bills as specified by the Commission.
- (11) If a consumer disputes the results of testing, the meter shall be tested at a third party testing facility selected by the consumer from the list of third party testing agencies approved by the Commission. If it is successfully established that the results of this test are contrary to the results of the test performed by the distribution licensee, then the cost of undertaking such test shall be borne by the distribution licensee. However, in case it is established that the results of this test are same as the results of the test performed by the distribution licensee in sub-rule (7), then the cost of undertaking such test shall be borne by the Consumer. The meter test results and the meter data shall be issued to the consumer after such test has been completed and the said results are final and binding on both the consumer and the distribution licensee.
- (12) The list of third party agencies approved by the Commission shall be available in their various offices as well as on the website of the distribution licensee.
- (13) Replacement of defective or burnt or stolen meters shall be done,-
- either on consumer's complaint or upon inspection by the distribution licensee, if the meter is prima facie found to be defective or burnt or stolen not due to causes attributable to the consumer, the licensee shall restore supply through a new meter at its own cost within the timelines as specified by the Commission;
 - if, after investigation, it is found that the meter has become defective or burnt or stolen due to causes attributable to the consumer, the necessary charges shall be recovered from the consumer as specified by the Commission;
 - within a time period, to be specified by the Commission not exceeding twenty-four hours in urban areas and seventy-two hours in rural areas by the distribution licensee.
- (14) Non-availability of meter shall not be a reason for delay in restoration of supply.
- (15) If the meter is installed outside the consumer's premises, distribution licensee shall be responsible for safe custody of the meter, and if the same is installed within the consumer's premises, the consumer shall be responsible for the safe custody of meter.
- 6. Billing and payment** – (1) Tariff for each category of consumers shall be displayed on distribution licensee's website and consumers shall be notified of change in tariff including fuel surcharge and other charges, a full billing cycle ahead of time, through distribution licensee's website as well as through energy bills.
- The distribution licensee shall prepare the bill for every billing cycle based on actual meter reading, except where pre-payment meters are installed, and the bill shall be delivered to the consumer by hand or post or courier or e-mail or any other electronic mode at least ten days prior to the due date of payment.
 - In case of non-receipt of original bill, the consumer shall be entitled to get a duplicate copy of the bill and shall also have the option to deposit self-assessed bill as per the procedure approved by the Commission:

Provided that the excess or deficit payment, as the case may be in case of self-assessment, shall be adjusted in the next bill or bills, as the case may be.

- (4) In case of pre-payment metering, the distribution licensee shall issue the bill, to the consumer, on his or her request.
- (5) The distribution licensee shall intimate the consumer about despatch of bill through SMS or email, or by both, SMS and e-mail, immediately and the intimation shall consist of the details of bill amount and the due date for payment.
- (6) The distribution licensee shall also upload the bill on its website on the day of bill generation:
Provided that the billing details of last one year for all consumers shall also be made available on the licensee's website.
- (7) The distribution licensee shall issue the first bill within a time period to be specified by the Commission, not exceeding two billing cycles, of energising a new connection where post payment meters are installed.
- (8) In case the consumer does not receive the first bill within such period, he may complain, in writing, to the distribution licensee and the distribution licensee shall issue the bill within a time period, not exceeding seven days.
- (9) The distribution licensee shall not generate more than two provisional bills for a consumer during one financial year and if the provisional billing continues for more than two billing cycles except under extraordinary situation due to force majeure, the consumer may refuse to pay the dues until bill is raised by the distribution licensee as per actual meter reading.
- (10) If any bill is served with a delay of such period as specified by the Commission, not exceeding sixty days, the consumers shall be given a rebate of two to five percent as specified by the Commission.
- (11) The information regarding the authority with whom grievance or complaint pertaining to bill can be lodged shall be provided along with the bill and the same shall also be made available on distribution licensees' website.
- (12) In case of vacation of premises, the distribution licensee shall arrange to take a special reading of the meter on receiving the consumer's written request and issue a final bill including all arrears till the date of billing and issue a No-Dues Certificate on receiving final payment, within a time period not exceeding seven days from the receipt of such final payment.

7. Method of payment of Bills .- (1) Consumer shall have the option to pay bills online or offline.

- (2) Bill amount of more than one thousand rupees or an amount specified by the Commission shall mandatorily be paid online. Commission shall specify a suitable incentive or rebate for payment through online system.
- (3) For bill amounts less than or equal to one thousand rupees consumer may pay the bill through cash or cheque or demand draft or electronic clearing system at designated counters of a bank or through credit or debit cards or online payment through distribution licensees' web portal or any digital mode of payment and any change or further addition in the mode of payment shall be more user friendly for the consumers than the prevailing system.
- (4) The distribution licensee shall establish online portal as well as sufficient number of collection centres or drop boxes at suitable locations with necessary facilities, where consumer can deposit the bill amount with ease.

8. Advance payment of bills.- (1) In case of post payment meters, when a domestic consumer gives prior information in writing about his continued absence from residence, the distribution licensee shall not send any notice or provisional bill to the consumer provided that the consumer pays the fixed charges for such period in advance and his supply line shall not be disconnected.

- (2) Interest shall be paid on advance amount paid under sub-rule (1), at such rate as may be decided by the Commission.

9. Disconnection and reconnection .- (1) (a) In case a consumer desires that his meter to be permanently disconnected, he shall apply for the same to the distribution licensee and the licensee shall arrange for a special meter reading and prepare a final bill.

- (b) The disconnection shall be done immediately after payment of the final bill. The balance amount due to any consumption between the final reading and the permanent disconnection, if any, may be adjusted

against the security amount with the distribution licensee. The remaining security deposit shall be refunded to the consumer within such period as specified by the Commission, not exceeding seven days.

- (2) In case the disconnection has been done on account of non-payment of past dues, the licensee shall reconnect the consumer's installation within such time as specified by the Commission, not exceeding six working hours of receipt of past dues and other charges as applicable.
- (3) Pre-payment meters will be designed to automatically cut off supply when the amount credited is exhausted. This shall however not be treated as a disconnection and the supply will be resumed whenever the meter is recharged.

10. Reliability of supply.- (1) The distribution licensee shall supply 24x7 power to all consumers. However, the Commission may specify lower hours of supply for some categories of consumers like agriculture.

- (1) The Commission shall specify the following parameters to maintain the reliability of supply by the distribution licensee; namely:-
 - (a) total duration and frequency of outages per consumer in a year -
 - a. System average interruption duration index (SAIDI);
 - b. System average interruption frequency index (SAIFI);
 - (b) the minimum outage time (in minutes) that the distribution licensee shall consider for the calculation of SAIDI or SAIFI, as the case may be

(2) The distribution licensee shall put in place a mechanism, preferably with automated tools to the extent possible, for monitoring and restoring outages.

11. Consumer as prosumer.-(1) While the prosumers will maintain consumer status and have the same rights as the general consumer, they will also have right to set up Renewable Energy (RE) generation unit including roof top solar photovoltaic (PV) systems – either by himself or through a service provider.

- (2) Renewable Energy (RE) generation unit may also be set up on other part of the premises of the prosumers, apart from the roof, however the total generation capacity of the RE unit shall not exceed the limit as specified by the Commission.
- (3) The Commission shall lay down regulations on Grid Interactive Roof top Solar PV system and its related matters with timelines of not exceeding six months from the date of notification of these rules, in case the same has not been notified.
- (4) The regulations on Grid Interactive Roof top Solar PV system and its related matters shall provide for net metering for loads up to ten kW and for gross metering for loads above ten kW.
- (5) The distribution licensee shall facilitate the process for setting up of RE generation system at prosumers' premises. In this regard, the licensee shall-
 - (a) create an online portal for receiving applications from prosumers for installation, interconnection and metering of distributed renewable energy systems or devices at their premises, and update the same on a regular basis;
 - (b) prominently display on its website and in all its offices, the following; namely:-
 - (i) detailed standardized procedure for installation and commissioning of roof top solar system;
 - (ii) a single point of contact to facilitate the consumers in installation of roof top solar system from submission of application form to commissioning.
 - (iii) address and telephone numbers of offices where filled-up application forms can be submitted;
 - (iv) complete list of documents required to be furnished along with such applications;
 - (v) applicable charges to be deposited by the applicant;
 - (vi) empanelled list of service providers for the benefit of consumers who want to install roof top solar PV system through service providers; and

- (vii) financial incentives to the prosumers, as applicable under various schemes and programmes of the Central and State Governments;
- (6) The distribution licensee shall ensure that-
- (i) application forms shall be accepted online or through hard copy;
 - (ii) in case the application form submitted in hard copy form, the same shall be scanned and uploaded on the website as soon as it is received and acknowledgement with the registration number for that application shall be generated and intimated to the applicant;
 - (iii) in case the application form received online through web portal of the distribution licensee, the acknowledgement with the registration number shall be generated on submission of application;
 - (iv) application shall be deemed to be received on the date of generation of acknowledgement with registration number; and
 - (v) the application tracking mechanism based on the unique registration number shall be provided by the distribution licensee through web-based application or any other mode to monitor the status of processing of the application like receipt of application, site inspection, meter installation and commissioning, etc.
- (7) The technical feasibility study shall be completed within the time period specified by the Commission, not exceeding twenty days and the outcome of the study shall be intimated to the applicant.
- (8) During the time period from the feasibility study till the completion of installation, in case, there is any requirement of upgradation of distribution infrastructure like augmentation of service line, distribution transformer capacity, etc., for installation of the required capacity of solar PV system, the same shall be carried out by the distribution licensee or consumer, as the case may be.
- (9) After installation of solar PV system, the consumer shall submit the installation certificate to the distribution licensee. The licensee shall complete signing of connection agreement, installation of meter and successful commissioning of the solar PV system within the timelines specified by the Commission which shall not be more than thirty days from the date of submission of the installation certificate. Formats of contract agreement and installation certificate shall be placed on web-portal of the distribution licensee.
- (10) Consumer shall have the option of purchasing the requisite meter himself which shall be tested and installed by the distribution licensee.
- (11) The timelines as specified by the Commission shall be adhered to by the distribution licensee. In case of delay, the licensee may take approval from the Commission in specific cases along with justification for the same.
- (12) In case of any delay on the part of distribution licensee without any just cause, the Licensee shall be liable to pay compensation to the consumer at a rate which shall not be less than five hundred rupees per day for each day of default.
- (13) The energy generated by prosumer shall be adjusted against energy consumed or the bill amount, depending on whether net metering or gross metering is applicable.
- (14) The distribution licensee shall pass on the financial incentives to the prosumers, as may be provided under various schemes and programmes of the Central and State Governments.

12. Standards of performance .- (1) The Commission shall notify the standards of performance for the distribution licensees as per sub-section (1) of section 57 of the Act and in consonance with the rules or regulations made thereunder.

(2) The Commission shall determine the compensation amount to be paid to the consumers by the distribution licensees for violation of standards of performance as per sub-section (2) of Section 57 of the Act.

13. Compensation mechanism .- (1) Consumer shall be automatically compensated for those parameters which can be monitored remotely when it can be successfully established that there is a default in performance of the distribution licensee.

(2) The Commission shall notify regulations for establishment of mechanism, by the distribution licensee, for automatic payment of compensation amount determined under the provisions of sub-section (2) of section 57 of the Act within six months from the notification of these rules.

(3) The Commission shall oversee that the distribution licensee designs and maintains its distribution system in such a way that there is a gradual increase in the list of parameters, which can be monitored remotely and for which automatic compensation can be made to the consumer.

(4) The standards of performance for which the compensation is required to be paid by the distribution licensee include, but are not limited to, the following, namely:-

- (i) no supply to a consumer beyond a particular duration, to be specified by the Commission;
- (ii) number of interruptions in supply beyond the limits as specified by the Commission;
- (iii) time taken for connection, disconnection, reconnection, shifting;
- (iv) time taken for change in consumer category, load;
- (v) time taken for change in consumer details;
- (vi) time taken for replacement of defective meters;
- (vii) time period within which bills are to be served;
- (viii) time period of resolving voltage related complaints; and
- (ix) bill related complaints.

(5) The distribution licensee, within six months from the date of notification of the regulations by the Commission under sub-rule (2), shall create an online facility on which consumers may register and claim the compensation amount. The information in this regard shall be widely circulated among consumers through appropriate means including mass media, bills, SMS, e-mails or by uploading on licensee's website.

(6) In all cases of compensation, the payment of compensation shall be made by adjustment against current or future bills for supply of electricity, within stipulated time from the determination of claim as specified by the Commission.

14. Call Centre for Consumer Services .- (1) For providing common services like new connection, disconnection, reconnection, shifting of connection, change in name and particulars, load change, replacement of meter, no supply, the distribution licensee shall establish a centralised 24x7 toll-free call centre with effect from such date as may be specified by the Commission.

(2) While other modes to provide services like paper application, email, mobile, website, etc., may continue, the licensees shall endeavour to provide all services through a common Customer Relation Manager (CRM) System to get a unified view of all the services requested, attended and pending, at the backend for better monitoring and analytics.

(3) The CRM shall have facilities for sms,email alerts, notifications to consumers and officers for events like receipt of application, completion of service, change in status of application, etc; online status tracking and auto escalation to higher level, if services are not provided within the specified time period.

15. Grievance redressal mechanism .- (1) The distribution licensee shall establish Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) under sub-section (5) of section 42 of the Act at different levels to cater the needs of the sub- division, division, circle, zone, company level. The forum shall be headed by an officer of the licensee of appropriate seniority. The forum shall consist of officers of the licensee and have not more than four members as consumer and prosumer representatives. The Appropriate Commission shall nominate one independent member who is familiar with the consumer affairs. The forum may be assigned different types of grievances depending on the nature of the grievance and the level at which it can be best resolved.

Provided that the manner of appointment and the qualification and experience of the persons to be appointed as member of the forum and the procedure of dealing with the grievances of the consumers by the Forum and other similar matters would be as per the guidelines specified by the Commission.

- (2) The licensee shall specify the time within which various types of grievances by the different levels of the forums are to be resolved. Normally, a grievance shall be decided within a period of thirty days and in any case not exceeding forty five days from the date of receipt of such grievance. The consumer aggrieved by the decision of sub-divisional or divisional or circle forum will have the option to approach the company level forum before making an appeal to the Ombudsman.
- (3) If a consumer's grievance is not redressed by the company level forum within the specified time or the consumer is not satisfied with the disposal of his grievance, he will be free to approach the Ombudsman appointed by the Commission.
- (4) The distribution licensee shall give wide publicity of the forum office, its complete address, contact details and procedure for registration of grievances through print and electronic media and notice boards of its various offices and also intimate the same to the consumers through electricity bills.
- (5) The distribution licensee shall set up a mechanism for monitoring of the grievances redressal.
- (6) The licensee will send quarterly reports to the Ombudsman and to the Commission, in respect of standards of performance, other performance parameters and consumer grievances related information showing the extent to which the time schedule has been followed in redressing the consumer grievances.
- (7) The performance of CGRF shall be monitored by the Commission.

16. General Provisions.- (1) The distribution licensee shall provide access to various services such as application submission, monitoring status of application, payment of bills, status of complaints raised, etc., to consumers through its website, web portal, mobile app and its various designated offices area-wise.

- (2) The distribution licensee shall provide all services such as application submission, payment of bills, etc., to senior citizens at their door-steps.
- (3) The details of scheduled power outages shall be informed to the consumers. In case of unplanned outage or fault, immediate intimation shall be given to the consumers through SMS or by any other electronic mode along with estimated time for restoration. This information shall also be available in the call center of the distribution licensee.
- (4) For creating proper awareness among consumers and licensee staff, the distribution licensee shall ensure to undertake the following steps, namely:-
 - (a) Manual of procedure for providing common services and handling customer grievances shall be made available for reference of consumers at every office of the distribution licensee and downloadable from its website
 - (b) The distribution licensee shall publish the guaranteed standards of performance along with compensation structure, information on procedure for filing of complaints, in the bills for month of January and July. If it is not possible to publish the same at the back of the bills, the distribution licensee shall publish it on a separate hand out and distribute it along with the bills.
 - (c) The distribution licensee shall arrange to give due publicity through media, TV, newspaper, website and by displaying in boards at consumer service related offices to bring awareness of consumer rights, standards of performance, compensation provisions, grievance redressal, measures for energy efficiency and any other schemes of the distribution licensee.
 - (d) The distribution licensee shall arrange to display feeder wise outage data, efforts made for minimising outages, prevention of theft or unauthorised use of electricity or tampering, distress or damage to electrical plant, electric lines or meter and results obtained during the year, on its website.

- (e) Whenever the existing meters are to be replaced by any new technology meters, the distribution licensee shall take adequate measures to create consumer awareness regarding the advantages of such replacement. Distribution licensee shall issue a public notice in at least four daily newspapers. Such information shall also be displayed in conspicuous manner on the distribution licensee's website and the distribution licensee shall indicate the area wise schedule of dates for replacement of such meter.

[F. No. 23/05/2020-R&R]

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2021

G.S.R. 448 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (z) of sub-section (2) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, to amend the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020, namely:-

1. (1) These rules may be called the Electricity (Rights of Consumers) Amendment Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rule), in rule 2, in sub-rule (1),-
 - (a) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-

'(ia) "gross-metering" means a mechanism whereby the total solar energy generated from Grid Interactive rooftop Solar Photovoltaic system of a Prosumer and the total energy consumed by the Prosumer are accounted separately through appropriate metering arrangements and for the billing purpose, the total energy consumed by the Prosumer is accounted at the applicable retail tariff and total solar power generated is accounted for at feed-in tariff determined by the Commission;'

(b) after clause (j), the following clauses shall be inserted, namely:-

'(ja) "net-billing or net feed-in" means a single bidirectional energy meter used for net-billing or net feed-in at the point of supply wherein the energy imported from the Grid and energy exported from Grid Interactive rooftop Solar photovoltaic system of a Prosumer are valued at two different tariffs, where-

 - (i) the monetary value of the imported energy is based on the applicable retail tariff;*
 - (ii) the monetary value of the exported solar energy is based on feed-in tariff determined by the Commission;*
 - (iii) the monetary value of the exported energy is deducted from the monetary value of the imported energy to arrive at the net amount to be billed (or credited / carried-over);*

(jb) "net-metering" means a mechanism whereby solar energy exported to the Grid from Grid Interactive rooftop Solar Photovoltaic system of a Prosumer is deducted from energy imported from the Grid in units (kWh) to arrive at the net imported or exported energy and the net energy import or export is billed or credited or carried-over by the distribution licensee on the basis of the applicable retail tariff by using a single bidirectional energy meter for net-metering at the point of supply;'
3. In the said rules, in rule 11, -
 - (a) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(4) The arrangements for net-metering, gross-metering, net-billing or net feed-in shall be in accordance with the regulations made by the State Commission, from time to time:

Provided that where the regulations does not provide for net-metering, net-billing or net feed-in, the Commission may allow net metering to the Prosumer for loads up to five hundred Kilowatt or upto the sanctioned load, whichever is lower and net-billing or net feed-in for other loads:

Provided further that in the case of Prosumers availing net-billing or net feed-in, the Commissions may introduce time-of-the-day tariffs whereby Prosumers are incentivised to install energy storage for utilization of stored solar energy by them or feeding into the grid during peak hours thus helping the grid by participating in demand response of the Discoms:

Provided also that in case of net-metering or net-billing or net feed-in, the distribution licensee may install a solar energy meter to measure the gross solar energy generated from the Grid Interactive rooftop Solar Photovoltaic system for the purpose of renewable energy purchase obligation credit, if any:

Provided also that the Commission may permit gross-metering for Prosumers who would like to sell all the generated solar energy to the distribution licensee instead of availing the net-metering, net-billing or net feed-in

facility and the Commission shall decided for this purpose the generic tariff for gross-metering as per tariff regulations:

(b) for sub-rule (13), the following sub-rule shall be substituted namely:-

“(13) The solar energy generated by prosumer shall be adjusted against energy consumed and bill amount as per regulations made by the Commission for Grid Interactive rooftop Solar Photovoltaic system.”

[F. No. 23/05/2020-R&R]

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number G.S.R. 818(E), dated the 31st December, 2020.

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2022

G.S.R. 306(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with clause (z) of sub-section (2) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020, namely:-

1. (1) These rules may be called the Electricity (Rights of Consumers) Amendment Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, in sub-rule (1),-
 - (a) after clause (f), the following clauses shall be inserted, namely:-
 - (fa) "customer average interruption duration index" means the average interruption duration of the sustained interruptions for those who experienced interruptions during the reporting period, as specified by the State Commission";
 - (fb) "customer average interruption frequency index" means the average interruption frequency of the sustained interruptions for those who experienced interruptions during the reporting period, as specified by the State Commission";
 - (b) after clause (j), the following clause shall be inserted, namely:-
 - (ja) "momentary average frequency interruption frequency index" means the average number of momentary interruptions per consumer occurring during the reporting period, as specified by the State Commission";
 - (c) after clause (m), the following clauses shall be inserted, namely:-
 - (ma) "system average interruption duration index" means the average duration of the sustained interruptions per Consumer occurring during the reporting period, as specified by the State Commission";
 - (mb) "system average interruption frequency index" means the average frequency of the sustained interruptions per Consumer occurring during the reporting period, as specified by the State Commission";
3. In the principal rules, in rule 10,-
 - (a) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3) In view of the increasing pollution level particularly in the metros and the cities with a population 100,000 and above, the distribution licensee shall ensure 24x7 uninterrupted power supply to all the consumers, so that there is no requirement of running the diesel generator sets and accordingly, the State Commission shall give trajectory of system average interruption frequency index and system average interruption duration index for such cities.

(4) The State Commission may consider the customer average interruption duration index, customer average interruption frequency index and momentary average interruption frequency index as additional indicators of reliability of supply and the minimum interruption time for calculation of additional reliability indicators shall be as specified by the State Commission and in case the interruption time is not specified by the State Commission, three minutes shall be considered as interruption time for calculating the additional reliability indicators.

(5) The State Commission shall have an online mechanism for reviewing and monitoring of reliability indices of distribution licensees and such Commission may consider a separate reliability charge for the distribution company, if they require funds for investment in the infrastructure for ensuring the reliability of supply to the consumers.

(6) The consumers, who are using the diesel generator sets as essential back up power, shall endeavor to shift to cleaner technology such as renewable energy with battery storage and the like

in five years from the date of commencement of these rules or as per the timelines given by the State Commission for such replacement based on the reliability of supply in that city covered under area of supply of the distribution licensee.

(7) The process of giving temporary connections to the consumers for construction activities or any temporary usage and the like shall be simplified by the distribution licensee and given on an urgent basis and not later than forty eight hours and within seven days in case augmentation of the distribution system is required and this shall avoid any use of diesel generator sets for temporary activities in the area of the distribution licensee.

(8) The temporary connection shall be through a prepayment meter or through consumer meters as defined in the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations as amended from time to time”.

[F. No. 23/05/2020-R&R]

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 818(E), dated the 31st December, 2020 and was last amended vide number G.S.R. 448 (E), dated 28th June, 2021.

ಕ್ರಮಾಂಕ:ಸೆಸ್/ತಾಂತ್ರಿಕ/ಸಪ್ಲೈ-04/E-446366/23-24/ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ

Cys-405

ದಿನಾಂಕ: 22 JUN 2023

1. ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಚಾವಿರನಿನಿ, ಮೈಸೂರು.
2. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮೈಸೂರು/ಹಾಸನ.
3. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, (ಆಂ.ಪ), ನಿಗಮಕಛೇರಿ, ಚಾವಿರನಿನಿ, ಮೈಸೂರು.
4. ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮೈಸೂರು/ಹಾಸನ.
5. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಲೆಕ್ಕಾಕಂದಾಯ/ ಹಣಕಾಸು/ಆಂ ಮತ್ತು ಮಾ.ಸಂ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಯೋಜನೆ/ಖರೀದಿ/ತಾಂತ್ರಿಕ, ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಚಾವಿರನಿನಿ, ಮೈಸೂರು.
6. ಎಲ್ಲಾ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾವಿರನಿನಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವ್ಯಕ್ತ.
7. ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಚಾವಿರನಿನಿ, ಮೈಸೂರು.
8. ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, (ಎಂ.ಐ.ಎಸ್) ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಚಾವಿರನಿನಿ, ಮೈಸೂರು ನಿಗಮದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು.
9. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಚಾವಿರನಿನಿ.
10. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಟಿ.ಎ.ಕ್ಯೂ.ಸಿ/ ಮಾಪಕ ಪರಿಣಿತರ ವಿಭಾಗ/ ಜಾಗೃತದಳ ಚಾವಿರನಿನಿ, ಮೈಸೂರು.
11. ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಚಾವಿರನಿನಿ.
12. ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು/ ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಇವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ರವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಡತ/ ಕಛೇರಿ ಕಡತ.

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)
ಚಾವಿರನಿನಿ, ಮೈಸೂರು